



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266622
CG-DL-E-03102025-266622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]
No. 285]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

(मामला सं. सीवीडी (ओआई) – 05/2025)

विषय : मलेशिया और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'क्लियर फ्लोट ग्लास' के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/36/2025-डीजीटीआर.—मेसर्स सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनपर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" या "नियमावली" भी

कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया गया है, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें, जहाँ उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है।

ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, मलेशिया सरकार और इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 09.09.2025 और 12.09.2025 को जाँच शुरूआत से पहले परामर्श आयोजित किए गए। प्राप्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और जाँच के दौरान उन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

ग. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "4 मिमी0 से 12 मिमी0 (दोनों सम्मिलित) तक की नामिनल मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जिसकी नामिनल मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)।
5. फ्लोट ग्लास में सामान्य ग्लास बनाने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर रेत, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), डोलोमाइट, चूना पत्थर, साल्ट केक (सोडियम सल्फेट) आदि शामिल होते हैं। अन्य सामग्रियों का उपयोग रंग, शोधन एजेंट के रूप में या ग्लास के भौतिक और रासायनिक गुणों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। कच्ची सामग्री को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिलाया जाता है, फिर उपयुक्त कलेट (अपशिष्ट काँच) के साथ नियंत्रित अनुपात में एक भट्टी में डाला जाता है जहाँ इसे लगभग 1500°C तक गर्म किया जाता है। कामन फ्लैट ग्लास की भट्टियाँ 9 मीटर चौड़ी और 45 मीटर लंबी होती हैं, और इनमें 1200 टन से अधिक काँच होता है। एक बार पिघलने के बाद, काँच का तापमान लगभग 1200°C पर स्थिर किया जाता है ताकि एकसमान विशिष्ट गुरुत्व सुनिश्चित हो सके।
6. इस उत्पाद का निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और ऑटोमोबाइल उद्योग आदि में प्रमुख रूप से उपयोग होता है। यह उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला काँच है। इसकी अंतर्निहित मजबूती, उच्च प्रकाशीय स्पष्टता, विरूपण-रहित चिकनी सतह आदि के कारण, विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस उत्पाद के अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं।
7. विचाराधीन उत्पाद को आईटीसी एचएस कोड: 70051090 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथापि इन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 के अंतर्गत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है।

घ. समान वस्तु

8. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएँ हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय करने योग्य हैं, और अतः, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तुएँ माना जा रहा है।

ङ. शामिल देश

9. यह आवेदन मलेशिया और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद पर कथित सब्सिडी के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जाँच के लिए संबद्ध देश मलेशिया और इंडोनेशिया हैं।

च. सब्सिडी कार्यक्रम

10. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों की सरकारों ने विभिन्न प्रतिकारी सब्सिडी कार्यक्रम चलाए हैं। आवेदक कंपनियों ने प्रस्तुत किया है कि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों को अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुओं और सेवाओं, तथा इक्विटी निवेश आदि के रूप में सब्सिडी प्राप्त हुई होगी - जो लाभकारी होगी। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते और प्रतिकारी शुल्क नियम, 1995 के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं, और ऐसी सब्सिडी संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा प्रदान की गई थीं और संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों और उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ हुआ होगा।

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाया जाता है।

I. मलेशिया के विरुद्ध आवेदक द्वारा अभिज्ञात स्कीमों की सूची

कार्यक्रम संख्या 1: बाज़ार विकास अनुदान

कार्यक्रम संख्या 2: विज्ञान निधि

कार्यक्रम संख्या 3: टेक्नो निधि

कार्यक्रम संख्या 4: इनो निधि

कार्यक्रम संख्या 5: क्रेडल निवेश कार्यक्रम

कार्यक्रम संख्या 6: अनुसंधान एवं विकास निधि का वाणिज्यीकरण

कार्यक्रम संख्या 7: निर्यात उत्कृष्टता कार्यक्रम

कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात ऋण पुनः निधियन

- कार्यक्रम संख्या 9: क्रेता ऋण गारंटी
- कार्यक्रम संख्या 10: अग्रणी का दर्जा
- कार्यक्रम संख्या 11: निवेश कर भत्ता
- कार्यक्रम संख्या 12: त्वरित पूंजी भत्ता
- कार्यक्रम संख्या 13: समूह राहत
- कार्यक्रम संख्या 14: टैरिफ संबंधी प्रोत्साहन
- कार्यक्रम संख्या 15: औद्योगिक भवन भत्ता (आईबीए)
- कार्यक्रम संख्या 16: संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता
- कार्यक्रम संख्या 17: मलेशियाई ब्रांड के प्रचार हेतु दोहरी कटौती
- कार्यक्रम संख्या 18: पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे में विनिर्माण और विनिर्माण संबंधी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
- कार्यक्रम संख्या 19: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर वापसी
- कार्यक्रम संख्या 20: बिक्री कर में छूट
- कार्यक्रम संख्या 21: आउटसोर्सिंग के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट विनिर्माण गतिविधियाँ
- कार्यक्रम संख्या 22: कलपुर्जों और उपभोज्य सामग्रियों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
- कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
- कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे सामग्री/घटकों पर आयात शुल्क से छूट
- कार्यक्रम संख्या 25: निर्यात संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
- कार्यक्रम संख्या 26: निर्यात कार्गो को बढ़ावा देने के लिए दोहरी कटौती
- कार्यक्रम संख्या 27: लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन
- कार्यक्रम संख्या 28: निर्यात में वृद्धि के लिए भत्ता
- कार्यक्रम संख्या 29: मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए कर छूट
- कार्यक्रम संख्या 30: आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के लिए कर प्रोत्साहन
- कार्यक्रम संख्या 31: लघु एवं मध्यम उद्यमों को रियायती ऋण
- कार्यक्रम संख्या 32: प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी

II. आवेदक द्वारा इंडोनेशिया के लिए अभिज्ञात सूची में की सूची

- कार्यक्रम संख्या 1: एलपीईआई (इंडोनेशिया एक्जिम बैंक) के माध्यम से निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात संवर्धन
- कार्यक्रम संख्या 2: अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त कटौती (300% तक)
- कार्यक्रम संख्या 3: उद्योग 4.0 / नवाचार अनुदान

- कार्यक्रम संख्या 4: बीपीपीटी केमेनरिस्टेक अनुसंधान एवं विकास सहायता (अनुदान + कर)
- कार्यक्रम संख्या 5: राष्ट्रीय नवाचार निधि के अंतर्गत स्टार्टअप और तकनीकी वित्तपोषण
- कार्यक्रम संख्या 6: केमेनपेरिन (एमओआई) के माध्यम से वाणिज्यीकरण सहायता
- कार्यक्रम संख्या 7: एमओटी द्वारा व्यापार संवर्धन अनुदान, निर्यात विकास प्रोत्साहन
- कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात कार्यशील पूंजी वित्तपोषण (एलपीईआई, राज्य बैंक)
- कार्यक्रम संख्या 9: इंडोनेशिया एक्जिम बैंक क्रेता ऋण योजना
- कार्यक्रम संख्या 10: कॉर्पोरेट आयकर अवकाश (5-20 वर्षों के लिए 100%)
- कार्यक्रम संख्या 11: कर छूट: 6 वर्षों में कर योग्य आय में 30% की कमी जमा मूल्यहास
- कार्यक्रम संख्या 12: अचल और अमूर्त संपत्तियों का त्वरित मूल्यहास
- कार्यक्रम संख्या 13: कर हानि कैरी-फॉरवर्ड समय विस्तार (10 वर्ष तक)
- कार्यक्रम संख्या 14: एसईजेड/केईके परिवेशों में सीमा शुल्क और टैरिफ प्रोत्साहन
- कार्यक्रम संख्या 15: औद्योगिक भवन परिसंपत्तियों के लिए त्वरित मूल्यहास
- कार्यक्रम संख्या 16: मशीनरी के लिए अतिरिक्त मूल्यहास या कर छूट
- कार्यक्रम संख्या 17: निर्यात संवर्धन और ब्रांडिंग (एमओटी) के लिए दोहरी कटौती
- कार्यक्रम संख्या 18: एसईजेड/केईके प्रोत्साहन (जैसे, बाटम, केंडल, बटांग) जिसमें कर और शुल्क छूट शामिल हैं
- कार्यक्रम संख्या 19: निर्यातकों के लिए शुल्क वापसी/वापसी योजनाएँ
- कार्यक्रम संख्या 20: निर्यात-संबंधी वस्तुओं और कच्ची सामग्री पर वैट छूट
- कार्यक्रम संख्या 21: आबद्ध क्षेत्रों में अनुबंधित विनिर्माताओं के लिए शुल्क मुक्त योजना
- कार्यक्रम संख्या 22: एमएफ विनियमों के अंतर्गत स्पेयर पार्ट्स के लिए आयात शुल्क छूट
- कार्यक्रम संख्या 23: विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट
- कार्यक्रम संख्या 24: कार्ट स्क्रीम: कच्चे सामग्री के आयात शुल्क में छूट
- कार्यक्रम संख्या 25: निर्यात-संबंधी व्ययों पर दोहरी कटौती
- कार्यक्रम संख्या 26: संभार-तंत्र/माल ढुलाई प्रोत्साहन कटौती
- कार्यक्रम संख्या 27: लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए केयूआर सॉफ्ट लोन और अल्ट्रा-माइक्रो फाइनेंसिंग
- कार्यक्रम संख्या 28: निर्यात निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन; निर्यात वृद्धि के लिए कर कटौती
- कार्यक्रम संख्या 29: एसईजेड/एफटीजेड क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए 100% सीआईटी छूट
- कार्यक्रम संख्या 30: पर्याप्त से कम मूल्य पर – गैस
11. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त स्कीमें सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबद्ध देशों की सरकार या ऐसे संबद्ध देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, से वित्तीय अंशदान शामिल है और ये स्कीमें प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये स्कीमें कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट एवं प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कुछ मामलों में, ये स्कीमें आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/या निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं।

12. कथित सब्सिडी में निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और निधियों या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है उसे छोड़ दिया गया है या एकत्र नहीं किया गया है; पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; निर्यात प्रदर्शन पर आकस्मिक संवितरण आदि।
13. उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य ऐसी सब्सिडी स्कीम के संबंध में जानकारी प्रदान करें जिसका उन्होंने लाभ उठाया हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य ऐसी सब्सिडी की जाँच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो जाँच के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा विद्यमान और उपयोग की गई पाई जा सकती हैं।

छ. घरेलू उद्योग

14. नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी प्राप्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को “घरेलू उद्योग” का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। ”

15. यह आवेदन मेसर्स सिसैकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् मेसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड (एआईएस) और गुजरात गार्जियन, जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। आवेदक भारत में कुल उत्पादन का 85% हिस्सा हैं और इसलिए, इसका एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं। आवेदकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्होंने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।
16. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि आवेदक घरेलू उत्पादक, सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग हैं और आवेदन सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ज. जाँच अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान आवेदन के लिए जाँच अवधि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 महीने) की प्रस्तावित है। क्षति की जानकारी जाँच अवधि और पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई के लिए प्रदान की गई है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

18. आवेदकों ने संबद्ध देशों से सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दोनों ही रूपों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित आयातों के कारण मूल्यहास और न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत पूरी तरह वसूल करने और उचित आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित रहा है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण नकद लाभ, पीवीआईटी और आरओसीई ऋणात्मक हैं। घरेलू उद्योग के मालसूची स्तरों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हैं।

ज. जाँच की शुरुआत

19. प्राधिकारी का मानना है कि विषयगत देश में विषयगत वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और ऐसे सब्सिडीयुक्त आयातों से उनकी मात्रा और मूल्य प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।
20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकरण एतद्वारा अधिनियम की धारा 9बी के साथ पठित नियम 6 के अनुसार घरेलू उद्योग को कथित सब्सिडी और परिणामी क्षति की सब्सिडी-रोधी जांच आरंभ करते हैं, ताकि कथित सब्सिडी के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ईमेल पत्तों ds-dgtr@gov.in और dir15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति consultant-dgtr@govcontractor.in and ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग पीडीएफ/एम एस वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एम एस एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रिया से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से ds-dgtr@gov.in और dir15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति consultant-dgtr@govcontractor.in और ad12-dgtr@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन सीवीडी के नियम 7(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।
28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण को दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना को प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय पाठ भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
30. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय अंश, गोपनीय अंश की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त छोड़ा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और ऐसी सूचना को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से सारांश रूप में दिया जाना चाहिए जो उस सूचना पर निर्भर रूप में हो, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है।
33. अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नियमावली, 1995 के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण के साथ कारणों का ऐसा विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।
34. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 26 के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 07 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
35. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उसके पर्याप्त और समुचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर और उसे स्वीकार किए जाने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।
38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ तथा अन्य जानकारी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग से पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

(Case No. CVD (OI)-05/2025)

Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “Clear Float Glass” originating in or exported from Malaysia and Indonesia.

1. **F. No. 6/36/2025-DGTR.**—An application has been filed by M/s Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Gold Plus Glass Industry Ltd., Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., and M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the “Applicants” or “domestic industry”), have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “CVD Rules” or the “Rules”) for imposition of countervailing duty investigation concerning imports of “Clear Float Glass” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or the “PUC”) originating in or exported from Malaysia and Indonesia (hereinafter referred to as the “subject countries”).

A. Allegation of subsidization

2. The Applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject countries, including the Governments of different Provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘Public Bodies. The Applicants have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies available in the public domain.

B. Consultation

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) pre-initiation consultations were held on 09.09.2025 and 12.09.2025 with the representatives of the Government of Malaysia and Government of Indonesia. The comments of the representatives of the Government of Malaysia and Indonesia have been taken on record.

C. Product under Consideration

4. The product under consideration in the present application is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive),” the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”).

5. Float glass uses common glass-making raw materials, typically consisting of sand, soda ash (sodium carbonate), dolomite, limestone, salt cake (sodium sulfate) etc. Other materials may be used as colourants, refining agents or to adjust the physical and chemical properties of the glass. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together with suitable cullet (waste glass), in a controlled ratio, into a furnace where it is heated to approximately 1500°C. Common flat glass furnaces are 9 m wide, 45 m long, and contain more than 1200 tons of glass. Once molten, the temperature of the glass is stabilized to approximately 1200°C to ensure a homogeneous specific gravity.
6. The product finds major uses in construction, refrigeration, mirror and automobile industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.
7. The product under consideration is classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware” under the ITC HS Codes: 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003,7004,7005,7007,7008,7009,7013,7015,7016,7018,7019 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975.

D. Like article

8. The Applicants have submitted that the subject goods produced by the Applicant companies and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and those produced by the Applicants. “Clear Float Glass” produced by the domestic industries and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘Like Article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

E. Countries involve

9. The application has been filed in respect of alleged subsidization of the product under consideration originating in or exported from Malaysia and Indonesia. Therefore, the subject countries for the present investigation are Malaysia and Indonesia.

F. Subsidy programs

10. The applicants have alleged that the Government in subject countries maintained various countervailable subsidy programs. The Applicant companies have submitted that there is sufficient evidence showing that the exporters of the subject goods may have received subsidies in the form of grants, loans, guarantees, taxes, export credits, goods and services, and equity infusions etc- which provide a benefit. The information provided by the Applicants indicate prima facie that the below mentioned programs constitute actionable subsidies as per the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the Countervailing Duty Rules, 1995, that such subsidies were provided by the Government of subject countries and that the exporters and producers of the subject goods in the subject countries may have benefitted from these subsidies.

Applicants have alleged that the following subsidy schemes/programs are availed by the producers of the product under consideration in subject countries.

I. List of Schemes/Programmes identified by the Applicant against Malaysia

1. The Market Development grant
2. Science Fund
3. Techno Fund
4. Inno Fund
5. Cradle Investment Program
6. Commercialization of research and development fund
7. Export excellence program
8. Export Credit Refinancing
9. Buyer Credit Guarantee
10. Pioneer Status
11. Investment Tax Allowance

12. Accelerated Capital Allowance
13. Group Relief
14. Tariff Related Incentive
15. Industrial Building Allowance (IBA)
16. Allowance for plants and Machinery
17. Double deduction for promotion of Malaysian brand
18. Incentive for manufacturing and manufacturing related service in East Cost Economic Corridor
19. Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
20. Sales Tax Exemption
21. Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities.
22. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables
23. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
24. Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
25. Double Deduction for Promotion of Exports
26. Double Deduction for Promotion of Export Cargo
27. Incentives for Small and Medium Enterprises
28. Allowance for Increased Export
29. Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones
30. Tax incentives for in-house R&D
31. Soft Loan to SME
32. Subsidies on Natural Gas

II. List of Schemes/Programmes identified by the Applicant against Indonesia

1. Export financing & export promotion via LPEI (Indonesia Exim bank)
2. Super deduction for R&D (up to 300%)
3. Industry 4.0 / innovation grants
4. BPPT Kemenristek R&D support (grant + tax)
5. Startup & tech funding under National Innovation Fund
6. Commercialization support via Kemenperin (MOI)
7. Trade promotion grants by MoT, export development incentive
8. Export working capital financing (LPEI, state banks)
9. Indonesia Exim bank buyer credit scheme
10. Corporate income tax holiday (100% for 5–20 yrs)
11. Tax allowance: 30% reduction of taxable income over 6 yrs plus depreciation
12. Accelerated depreciation of fixed and intangible assets
13. Tax loss carry-forward extension (up to 10 years)
14. Customs and tariff incentives in SEZ/KEK environments
15. Accelerated depreciation for industrial building assets
16. Additional depreciation or tax allowance for machinery
17. Double deductions for export promotion and branding (MoT)
18. SEZ/KEK incentives (e.g. Batam, Kendal, Batang) including tax & duty waivers
19. Duty drawback / refund schemes for exporters

20. VAT exemption on export-related goods and raw materials
 21. Duty free scheme for contract manufacturers in bonded zones
 22. Import duty exemption for spare parts under MF regulations
 23. Duty exemption on capital goods for manufacturing
 24. KITE scheme: raw material imports duty exemption
 25. Double deduction on export-related expenses
 26. Logistics / freight promotion deduction
 27. KUR soft loans and ultra-micro financing for SMEs
 28. Incentives tied to export performance; tax deduction for export growth
 29. 100% CIT exemption for exporters in SEZ/FTZ areas
 30. Less than Adequate remuneration – Gas.
11. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of the subject countries or other regional or local governments of such subject countries, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable.
 12. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; disbursement contingent on export performance etc.
 13. The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

G. DOMESTIC INDUSTRY

14. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

“‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”
15. The application has been filed by M/s Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Gold Plus Glass Industry Ltd., Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., and M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd. Apart from the Applicants, there are two other producers in India, viz. M/s Asahi India Glass Ltd (AIS) and Gujarat Guardian, who had commenced production of the subject goods. Applicants account for 85% of the total production in India and therefore, account for a major proportion. It is further submitted by the applicants that they have not imported the subject goods from the subject countries. Moreover, the Applicants are not related to any importer or exporter of the subject goods during POI.
16. On the basis of information available on record, it is noted that the Applicant domestic producers constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 6(3) of the CVD Rules, 1995.

H. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the present application is proposed from April 2024 to March 2025 (12 months) as the period of investigation. The injury information has been provided for the period of investigation and three preceding years, that is 2021-22, 2022-23 and 2023-24.

I. Allegation of Injury and Casual Link

18. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the subsidized imports from the subject countries. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as in relative terms. The capacity utilization of the domestic industry has declined. The price suppression and depression caused by the alleged subsidised imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of returns. The alleged subsidised imports of subject goods from subject countries have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT and

ROCE are negative. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicant's *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged subsidised imports from subject countries.

J. Initiation of the Investigation

19. The Authority finds that there is *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject country and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects.
20. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicants substantiating the subsidization and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-subsidy investigation into the alleged subsidisation and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9B of the Act read with Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged subsidies and to recommend the amount of Anti subsidy/countervailing , which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Submission of Information

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses ds-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in a copy to consultant-dgtr@govcontractor.in and dir15-dgtr@gov.in . It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address ds-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to consultant-dgtr@govcontractor.in and dir15-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The non-confidential summary must have sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 26 of this initiation notification.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request there to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority